मु.मंत्री ने अलवर में सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की

- **मुख्यमंत्री भजनलाल, रामगढ़ विधायक जुबेर खान, जिनका 14 सितम्बर को देहान्त हुआ है, के घर गए तथा परिजनों को ढांढस बंधाया।**
- **मुख्यमंत्री पूर्व केन्द्रीय मंत्री रोहिताश शर्मा के घर भी गए तथा उनके पुत्र के निधन पर शोक संतप्त परिवार से संवेदना जताई।**

अलवर, 16 सितम्बर (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आर.एस.एस. के कार्यालय ‘‘केशव कृपा’’ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की।

मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ विधायक स्व. जुबेर खान के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके पुत्र आदिल खान एवं आर्यन खान व परिजनों को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ विधायक स्व. जुबेर खान का लम्बी बीमारी के बाद शनिवार 14 सितंबर को प्रातः देहांत हो गया था।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रोहिताश शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनके पुत्र स्व.विकेश कुमार शर्मा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शोक संतप्त परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त कर ढांढस बंधाया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हैलीपैड पर स्वागत के दौरान वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, विधायक डॉ. जसवंत यादव, महन्त बालकनाथ, रमेश खींची, देवीसिंह शेखावत एवं नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व मंत्री हेमसिंह भडाणा, पूर्व विधायक जयराम जाटव, बनवारी लाल सिंघल व संजय नरूका, बन्नाराम मीणा, जय आहूजा, मोहित यादव, गोरधन सिंह सिसोदिया, मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, पं. जलेसिंह सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति मौजूद रहे।

‘वर्तमान मोदी सरकार’ ‘‘यू-टर्न्स’’ की सरकार है’

मोदी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने व्यंग्य कसा

- **‘‘लेटरल एन्ट्री’’ वक्फ संशोधन विधेयक, प्रसारण विधेयक, नैशनल पैन्शन सिस्टम, जैसे कई उदाहरण हैं जब पिछले सौ दिनों में सरकार विधेयक/प्रोसेस शुरु कराकर पीछे हट गई।**

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। कांग्रेस ने आज जोर देते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में, देश की जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में हर मोर्चे पर बुरी तरह असफल रही है।

पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए, कांग्रेस के सोशल मीडिया की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘‘आज नरेन्द्र मोदी सरकार के सौ दिन पूरे हुए हैं। यह राष्ट्र बहुत सारे मुद्दों का सामना कर रहा है। मोदी सरकार ने देश को हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल कर दिया है।’’

सत्तारूढ़ दल के 100 दिनों के काम-काज का हवाला देते हुए कहा, ‘‘यह सरकार यू-टर्न वाली सरकार रही है। सीधी भर्ती (लेटरल ऐन्ट्री) से लेकर, वक्फ (संशोधन) विधेयक, ब्रॉडकास्ट (सर्विस रेग्यूलेशन) बिल, इन्डैक्सेशन, एन.पी.एस. (नेशनल पेंशन सिस्टम) जिसकी वजह अब यू.पी.एस. (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लाई गई है, तक कई फैसलों पर सरकार के कदम पीछे हटाए हैं। यू-टर्नों वाली सरकार रही है। यह यू-टर्न सरकार रही है।’’

रेल-दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए श्रीनेत ने कहा, ‘‘वास्तविकता यह है कि इन दिनों में भारतीय रेलवे अपने सबसे खराब दौर में रही है। इन दिनों में 38 रेल-दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21 मौतें बताई गई हैं।’’

रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, इस देश के रेल मन्त्री इन्हें छोटी-मोटी दुर्घटनाएं बता रहे हैं तथा लगातार रील्स बना रहे हैं।’’

प्रधानमन्त्री मोदी पर हमला बोलते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वास्तविकता यह है कि आपके कार्यकाल में बने हुए, आपके निर्देशन में बनाए हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहे वे पुल हों, सड़कें हों, प्रतिमाएं हों या फिर हवाई अड्डे हों पूरी तरह से ढह गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं।

नया संसद भवन, जो टपक रहा था, से लेकर अयोध्या के राम मन्दिर, जिसके गर्भगृह में पानी टपक रहा था, तक, मुम्बई में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा तक सबका यही हाल है। ...क्या यह सब भ्रष्टाचार का सबूत नहीं हैं, तो और क्या है?’’

चार बांग्लादेशी भारत में घुसने की कोशिश में गिरफ्तार

ढाका, 16 सितंबर। बंगलादेश के पत्रकार मोजम्मिल बाबू और श्यामल दत्ता समेत चार लोगों को मैमनसिंह में धोबौरा सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के प्रयास में हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्टों में सोमवार को यह जानकारी दी गयी। स्थानीय अखबार ‘‘द डेली स्टार’’ ने धोबौरा थाने के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद चान मिया के हवाले से बताया कि स्थानीय लोगों ने सुबह धोबौरा-पुरबधाला सीमा क्षेत्र से चार लोगों और एक निजी कार को पकड़ लिया। रिपोर्ट के अनुसार बाबू एकटोर टीवी के प्रबंध निदेशक एवं प्रधान संपादक हैं और दत्ता जटिया प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव हैं।

‘मोदी सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि सरकार ने सबका प्रभावी विकास किया है। आज अनेक प्रोजेक्ट विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर रहे हैं।

तमिलनाडु के मु.मंत्री स्टालिन प्र.मंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी प्रमाणित होती है कि दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियाँ भाषा के मामले में एक साथ हैं। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केन्द्रीय सहायता केवल उन्हीं राज्यो को दी जाएगी, जो शिक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत, हिन्दी के तीसरी भाषा रखने पर सहमत होंगे। शिक्षा मन्त्री द्वारा इस बिन्दु पर जोर देने से राज्य में चिन्ता पैदा हो गई है तथा मुख्यमन्त्री इस सुझाव को दरकिनार करने के लिए दृढ़निश्चयी प्रतीत हो रहे हैं।

निवेश हासिल करने के उद्देश्य की गई एक पखवाड़े की अमेरिका यात्रा से वापस आते ही, मुख्यमंत्री ने एक बयान मे शनिवार को कहा कि वे जल्दी ही प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे।

जिस दूसरे मुद्दे को लेकर राज्य एवं मुख्यमंत्री स्टालिन चिन्तित हैं, वह है चेन्नई के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहयोग। तथ्य यह है कि इस मामले में राज्य के दावो तथा केन्द्र की वस्तुस्थिति-सम्बन्धी समझ मे भिन्नता है तथा मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी इस अन्तर का समाधान निकालना चाहते हैं, जिससे तमिलनाडु को भी चेन्नई शहर में अत्यावश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता मिले। इस सन्दर्भ में, मुख्य मुद्दा सी.एम.आर.एल. के दूसरे चरण के लिये फन्डिग का है। जैसा कि तमिलनाडु के वित्तमन्त्री थंगम थेन्नारासू ने हाल ही में कहा कि राज्य इस प्रोजेक्ट पर 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च कर चुका है, लेकिन केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण ने इस राशि को अमान्य करते दिए गए 21,000 करोड़ रुपये के ऋण में से केवल 5,880 करोड़ रुपये ही काम में लिये हैं। मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता माँग रहे हैं जिससे मेट्रो प्रोजेक्ट एक्स्टेंशन का काम समय पर पूरा हो जाये। लेकिन बात केवल इन दो मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में, स्टालि, इन दोनों बिन्दुओं के बाद, संघवाद तथा स्वायत्तता पर पहुँचेगे तथा ये दोनों बिन्दु राष्ट्रीय बहस के विषय बनेंगे। स्टालिन स्वयं को तमिलनाडु के हितों के इकलोते संरक्षक के रूप में पहले ही स्थापित कर चुके हैं तथा केन्द्र सरकार की उन नीतियों को पुरजोर विरोध करते रहे हैं, जिनके बारे में वे ऐसा मानते हैं कि ये नीतियाँ तमिलनाडु की अद्वितीय संस्कृति तथा राजनैतिक पहचान को प्रभावित कर सकती हैं। तमिलनाडु तथा विपक्ष शासित अन्य राज्य निर्णय लेने के मामले में ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं।

ममता बनर्जी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अफसरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि इसमें उच्च अधिकारी लिप्त हैं, जिनकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता।

सवाल पूछा जा रहा है कि किसके निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। सी.बी.आई. एक-एक सिरा जोड़कर आगे बढ़ रही है।

कर्नाटक में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाला कानून यहां भी लगाया जाए।

लेकिन फिल्म उद्योग के सूत्रों ने बताया कि फिल्म उद्योग इस मसले पर बटां हुआ है। एक गुट का कहना है कि फिल्म उद्योग इस मसले को खुद हल कर सकता है। सरकार को बीच में आने की जरूरत नहीं है। फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों ने राज्य के गृह मंत्री से भी मुलाकात की और फिल्म उद्योग के महिला की सुरक्षा को मद्देनज़र काम करने लायक माहौल सुधारा जाए।

आज की मीटिंग में कन्नड़ सुपर स्टार सुदीप, संजना गलरानी, कविता लंकेश और दिव्या सपादना भी मौजूद थे। उन्होंने अपना पक्ष भी रखा और सारे मामले को देखने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनाने की मांग की तथा महिला सुरक्षा के हित ने इण्डस्ट्री का कामकाज सुधारने के लिए गाइडलाइन्स बनाने की मांग की।

एक बार फिर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सर्विस’’ के एजेंट ने देखा कि लगभग 400 गज की दूरी पर झाड़ियों के बीच से एक राइफल की नाल दिख रही थी। पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने बताया कि एक एजेंट ने गोली चलाई जिसके बाद वहां मौजूद बंदूकधारी राइफल वहीं फेंककर एक एसयूवी में सवार होकर भाग गया। उन्होंने बताया कि राइफल के साथ दो बैकपैक, निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दूरबीन और एक कैमरा भी मिला है। बाद में उस व्यक्ति को अधिकारियों ने पकड़ लिया। हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वह सुरक्षित और ठीक हैं। ट्रंप ने अपने समर्थकों को भेजे एक ईमेल में कहा, ‘‘मेरे आस-पास गोलीबारी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इससे पहले कि अफवाहें नियंत्रण से बाहर हो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित और ठीक हूं।

राजू ठेहट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हत्याकांड में लिप्त नहीं माना जा सकता। प्रकरण में ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है। इसके अलावा उसे करीब एक साल दस माह से किशोर गृह में रखा गया है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलार्थी को जमानत का लाभ दिया है।

गौरतलब है कि 3 दिसंबर, 2022 को चार बदमाशों ने राजू ठेहट की उसके सीकर स्थित घर के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। घटना के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

फिलहाल सीकर की अदालत में करीब 27 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है।

‘एक-एक अपराधी को पकड़कर कानून के हवाले करेंगे’

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसों में साजिश की चर्चा पर कठोर टिप्पणी की

- **रेल मंत्री ने कहा, मैं चेतावनी देता हूँ हम हर अपराधी को पकड़ेंगे, देश के दो करोड़ लोग जो प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा के साथ किसी को भी खेलने नहीं देंगे।**

नयी दिल्ली, 16 सितंबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसों के पीछे साजिश की चर्चा के बीच आज रोष जताते हुए कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले एक एक अपराधी को पकड़ कर कानून के हवाले किया जाएगा।

वैष्णव ने रेल हादसों के पीछे साजिश होने को लेकर पहली बार ऐसी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के कॉन्क्लेव ‘‘चौपाल’’ में रेल दुर्घटनाओं को लेकर सवालों के जवाब में कहा, ‘‘मैं उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता हूं। हम ऐसा करने वाले एक-एक को पकड़ेंगे, एक-एक के पीछे जाएंगे। देश के जो दो करोड़ यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, जिम्मेदारी के साथ उनकी सुरक्षा करेंगे। किसी को भी यात्रियों की सुरक्षा के साथ खेलने नहीं देंगे। हमें इतना चौकन्ना रहना है कि इस तरह के हर प्रयास को विफल कर सकें।’’

उल्लेखनीय है कि इन दिनों रेलवे ट्रैक पर साजिश के तहत कई तरह की चीजें रखे जाने की रिपोर्टें आ रही हैं। इसे लेकर रेल मंत्री ने ऐसी साजिश रचने वालों को चेताया है।

वैष्णव ने कहा आज से दस साल पहले देश में हर साल 171 रेल दुर्घटनाएं होती थीं लेकिन आज यह आंकड़ा घट कर 40 तक आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी दिन रात मेहनत करके ढांचागत बदलाव करने पर फोकस है जिससे कि दुर्घटनाओं की संख्या 40 से भी कम करें। आने वाले दिनों में हम और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। यात्रियों की सुरक्षा को और सुनिश्चित करेंगे।

बांग्लादेश को 200 एकड़ जमीन लौटाई जाएगी

सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच हुई बैठक में फैसला लिया गया

- **बांग्लादेश की 200 एकड़ जमीन नदी के कटाव के कारण भारत में चली गई थी इसके अलावा भारत की 40 एकड़ जमीन बांग्लादेश में चली गई थी।**

ढाका, 16 सितंबर। बॉर्डर गार्ड बंगलादेश (बी.जी.बी.) और भारत के सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) की बैठक में 200 एकड़ भूमि बंगलादेश को लौटाने का निर्णय लिया गया, जो पहले नदी के कटाव के कारण भारत में चली गयी थी। रिपोर्ट के मुताबिक बी.जी.बी. और बी.एस.एफ. के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रविवार को हुई बैठक में विवादित भूमि का फिर से सर्वेक्षण करने और इसे सही मालिकों को लौटाने का संयुक्त निर्णय लिया गया।

दौलतपुर उपजिला में रामकृष्णपुर संघ के चालिशपारा क्षेत्र में स्थित विवादित भूमि पद्मा नदी के मार्ग में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विवाद में रही है, जिसने तीन किलोमीटर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तंभों को अव्यवस्थित कर दिया है। इस साल की शुरुआत में किये गये सर्वेक्षण में यह मामला सामने आया था।

बी.जी.बी. की 47वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल एम. महबूब मुर्शेद रहमान ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गत 10 फरवरी को सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि, लगभग 200 एकड़ बंगलादेश की भूमि भारतीय क्षेत्र में तथा करीब 40 एकड़ भारतीय भूमि बंगलादेश क्षेत्र में चली गई है। दोनों देश अब अक्टूबर में आधिकारिक रूप से सीमाओं को सही करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवादित भूमि का पुनः सर्वेक्षण करने तथा उसे उसके वास्तविक मालिकों को लौटाने पर सहमति बनी है।

बैठक में सीमा पर हत्याओं को रोकने तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने जैसे व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल रहमान ने किया, जबकि रोशनबाग बटालियन के कमांडेंट विक्रम देव सिंह ने बी.एस.एफ. का प्रतिनिधित्व किया।

लेफ्टिनेंट कर्नल रहमान ने जोर दिया कि जब तक पुनः सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी विवादित भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने सीमा पर हाल ही में हुई हत्याओं के खिलाफ बंगलादेश का कड़ा विरोध भी जताया और बीएसएफ से निर्दोष नागरिकों को हिरासत में लेने से बचने तथा विशेष रूप से दुर्गा पूजा से पहले अवैध सीमा पार गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया।

हिमाचल में लागू होगी बागवानी नीति

शिमला, 16 सितंबर। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ ाना और प्रदेश को फल राज्य बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,292 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य के सात जिलों में छह हजार हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। उन्होंने अंतर-फसलीय खेती पर बल देते हुए कहा कि दो चरणों में अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन तथा कटहल के पौधे रोपे जाएंगे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय** : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **बीकानेर कार्यालय** : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 **चूरू कार्यालय** : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908